है। इन व्यापक योजनाओं में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में किए जाने वाले विशिष्ट अपरदन विरोधी निर्माण कार्यों के लिए सुझाव शामिल हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में मात्र गंगा नदी के कारण हो रही अपरदन की समस्या के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विशिष्ट अध्ययन नहीं किए गए हैं।

Foodgrain production

327. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that foodgrain output in 1998-99 is likely to fall short of target of 200 million tonnes;

(b) if so, what was total foodgrain production during the last 3 years, till date, group-wise;

(c) what are the reasons for fall of Government's target of doubling foodgrain production over the Ninth Plan period; and

(d) whether Government would be able to meet demand of foodgrains of all sectors in the country indicating the concrete steps taken so far to increase the foodgrains production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) The total foodgrain production during last three years and during current year by major crop groups is as under:

(million tonnes)

Crop Group	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
Rice	76.98	81.73	82.30	82.23
Wheat	62.10	69.35	65.90	69.13
Coarse Cereals	29.03	34.11	31.16	29.91
Cereals	168.11	185.19	179.36	180.47
Total Pulses	12.31	14.25	13.07	14.78
Total Foodgrain	180.42	199.44	192.43	195.25

(c) The Government does not envisage doubling foodgrain production during the Ninth Plan period. The plan is to double the food production in next ten years.

(d) In order the increase production of foodgrains, the Government is implementing crop specific centrally sponsored schemes/programmes under which incentives are provided to farmers for use of quality seeds and location specific high yielding/hybrid varieties, application of integrated pest management, propagation of scientific water management including micro irrigation, improved farm implements etc. Besides, field demonstration on farmers holdings including training of farmers and farm labourers are organised for effective transfer of technology. Further, under the national agenda for governance, the Government has given fresh thrust to double the food production in next ten years adopting regionally differentiated growth strategies, creation of farming infrastructure and more efficient use of resources. With the concerted efforts being made, it would be

possible for the Government to meet demand for foodgrains.

मालपा त्रासदी से प्रभावित लोगों का पुनर्वास

328. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री 17 दिसम्बर, 1998 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 272 के ए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूद्र प्रयाग (चमोली जिले) की उखीमठ तहसील के 20 से अधिक गांवों को असुरक्षित घोषित किया गया है तथा उनके स्थान पर नये गांवों के निर्माण हेतु आयुक्त, गढ़वाल द्वारा गुप्तकाशी के पास भूमि उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उखीमठ त्रासदी से पीड़ित इन गांवों के पुनर्निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के साथ चर्चा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए इस संबंध में उससे कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया।

दलहन प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन

329. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री 10 दिसम्बर, 1998 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1266 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने जिलों में दलहन प्रोत्साहन योजना लागू करने का विचार है;

(ख) क्या इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या इस योजना को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर उत्तराखंड/उत्तरांचल में भी लागू करने का विचार है जहां लोबिया, उड़द, सोयाबीन, तूर आदि दलहन फसलें प्रचुर मात्रा में उगायी जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) तिलहन तथा दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना की स्कीम 295 जिलों को कवर करते हुए 24 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से सितम्बर, 1996 में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत 44.905 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्राप्त किया गया है। प्रस्ताव में बीज वितरण एवं सिंचाई (डीजल सप्लाई पर राजसहायता) पर राजसहायता की अनुमति देने के लिए 1996-97 से 2001-2002 तक ग्रीष्म कालीन दलहन उत्पादन के विशेष कार्यक्रम हेतु सहायता शामिल थी। लेकिन प्रस्ताव राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के मानदण्डों के अनुसार नहीं था, अतः इसे स्वीकार नहीं किया गया। बहरहाल हमने 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को निम्न राशियां निर्मुक्त की हैं:—

वर्ष	निर्मुक्त राशि
1996-97	713.50 लाख रुपये
1997-98	877.25 लाख रुपये
1998-99	550.00 लाख रुपये (आज तक)

(ग) और (घ) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 49 जिले कवर किए गए हैं। इनमें से निम्न जिले पहाड़ी क्षेत्रों में हैं:—

1. नैनीताल
2. पिथौरागढ़
3. पौड़ी गढ़वाल
4. उधम सिंह नगर
5. चम्पावत

"नैफेड" के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

330. **श्री रमा शंकर कौशिक:**
श्री ईश दत्त यादव:
प्रो॰ रामगोपाल यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "नैफेड" के प्रबंध निदेशक पर लगे भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोपों की जांच कराई है या कराने का विचार कर रही है;